1.46 लाख शिकायतें रिजर्व बैंक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली में बैंकों के खिलाफ दर्ज कराई हैं ग्राहकों ने सेवाओं से नाखुश होकर। रिजर्व बैंक ने पिछले साल यह व्यवस्था शुरू की थी। यह आंकड़े 1 जुलाई से 22 दिसंबर, 2019 के बीच के हैं।

भारत के लिए अहम है एस-400 वायु रक्षा प्रणाली

एक साथ कई तरह के लक्ष्यों को पहचान कर उन्हें मार गिराने में सक्षम रूस की एंटी बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एस 400 साल 2025 में भारत के जखीरे में शामिल होगा। भारत को दी जाने वाली इस प्रणाली का उत्पादन रूस ने शुरू कर दिया है। एस 300 का यह उन्नत संस्करण है। एल्माज-एंते द्वारा तैयार की गई दुनिया की सबसे आधुनिक और सटीक एंटी मिसाइल डिफेंस प्रणाली 2007 से रूसी सेना में शामिल है।

₹39,000 करोड़ का है सौदा

400 किमी मारक क्षमता

5 एस-400 मिसाइल सिस्टम खरीदेगा भारत

60% रूस से सैन्य हथियारों की खरीद

15 अक्टूबर, 2016 को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इस प्रणाली को लेकर भारत और रूस के बीच औपचारिक वार्ता हुई। पांच अक्टूबर, 2018 को दोनों देशों ने 39 हजार करोड़ के इस रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए।

क्या है एस-400 मिसाइल

रूस की एस-400 ट्रायंफ दुनिया का सबसे आधुनिक वायु डिफेंस प्रणाली है। एक साथ कई तरह के लक्ष्यों की पहचान और उसे मार गिराने में सक्षम है। सभी तरीके के विमानों, मिसाइलों और मानवरहित विमानों को एक साथ भेद सकती है। यह प्रणाली कई तरह के आधुनिक रडारों, कंट्रोल सिस्टम्स और विभिन्न प्रकार की मिसाइलों से युक्त है। इसके रडार एक हजार किमी दूर से ही किसी लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं। साथ ही स्वत: चालित और नियंत्रित तरीके से दूरी के लिहाज से मिसाइल का संधान कर उसे अचूक रूप से मार गिराते हैं। नाटो देशों ने इसे एसए 21 ग्रोलर नाम दिया है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर दूर से हमला कर सकती है। निर्देश मिलने के पांच मिनट के अंदर इसमें एक साथ तीन मिसाइल दागी जा सकती हैं। ये सुपर फाइटर जेट समेत 100 एयरबोर्न (हवाई लक्ष्य) को ट्रैक करते हुए एक साथ छह पर निशाना साध सकती है।

पुराना रक्षा सहयोगी

1953 के बाद भारत लगातार रूस से सैन्य हथियार खरीदता रहा है और कुल सैन्य हथियारों में से 60 फीसद रूस से खरीदे जाते हैं। सेना में परमाणु पनडुब्बी आइएनएन चक्र, सुपसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, मिग और सुखोई लड़ाकू विमान, आइएल परिवहन विमान, टी-72 और टी-90 टैंक व विक्रमादित्य विमान वाहक युद्धपोत शामिल हैं। पुतिन जब भारत दौरे पर आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप भारत के किसी बच्चे से पूछिए तो यही कहेगा कि रूस ही भारत का मित्र है।

एस-400 प्रणाली की जरूरत

भारत में वायु रक्षा प्रणाली अन्य देशों की तुलना में पुरानी है जिनमें ज्यादातर सोवियत युग के मिग जेट हैं। एस-400 रूस की सबसे एडवांस और सबसे शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली है जो 2007 में रूसी सेना में तैनात की गई थी। ये अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान एफ-35 को भी समय रहते गिराने की क्षमता रखती है। चीन ने 2015 में सबसे पहले रूस से एस-400 रक्षा प्रणाली खरीदी थी और ये चीनी सेना में शामिल है। पाकिस्तान और चीन की तरफ से सुरक्षा और ये दोहरे युद्ध के मामले में यह महत्वपूर्ण है।

एस-400 के रास्ते में आई बाधाएं

अमेरिका का काटसा कानून कहता है कि अगर कोई देश रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ सैन्य समझौता करता है तो वह अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकता है। ऐसे में रूस से समझौता काटसा कानून का उल्लंघन होगा जो भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में ले आएगा।

भारत को हथियार निर्यात में देशों का हिस्सा

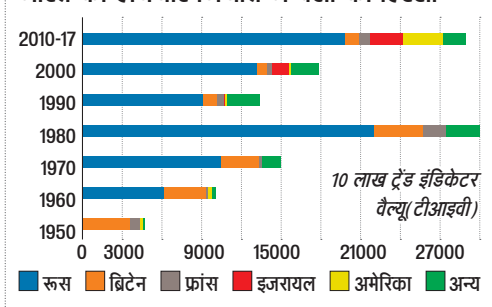

बड़े काम की है ये रक्षा प्रणाली

- प्रतिष्ठित पत्रिका इकोनामिस्ट ने रूस की एस-400 या ट्रायंफ एंटी बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को वर्तमान में दुनिया की सबसे बेहतर प्रणाली बताया।
- दुनिया भर के हथियारों, और देशों के अस्त्र-शस्त्रों के जखीरों का लेखा जोखा रखने वाली संस्था सीपरी ने इसे वर्तमान में मौजूद सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से नवाजा।
- दुनिया के आधा दर्जन देशों की सेनाओं में ये प्रणाली शामिल हैं या शामिल होने की प्रक्रिया में है।

न्यूज गैलरी

लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी सेना उप प्रमुख नियुक्त

नई दिल्ली : भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी सेना के नए उप प्रमुख होंगे। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले वह अपना प्रभार संभालेंगे। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरवाने के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रोन्नत होने के बाद से यह पद खाली था। कपूरथला सैनिक स्कूल और नेशनल डिफेंस अकादमी से शिक्षित सैनी जून 1981 में जाट रेजिमेंट में कमीशंड हुए थे। दक्षिणी कमान के मुख्यालय पुणे में जाने से पहले वह कई प्रमुख भूमिकाओं में रह चुके हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद निरोधक बल को भी वह कमांड कर चुके हैं। इसके साथ ही वह नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड के प्रशिक्षण केंद्र में हथियार प्रशिक्षक नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीनियर डाइरेक्टिंग स्टाफ और देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में कमांडेंट रह चुके हैं। (आइएएनएस)

एसके सैनी। फाइल

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए 30 अप्रैल तक करें आवेदन

नई दिल्ली : भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू की है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के क्षेत्र में यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नामांकन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 है। पुरस्कार के लिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://nationalunityawards.mha.gov.in पर नामांकन स्वीकार किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा, 'भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान तथा एक एवं सशक्त भारत की सोच को मान्यता देगा।' इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस पर की जा सकती है। 31 अक्टूबर सरदार पटेल का जन्मदिन है और इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। (एएनआइ)

कलबुर्गी हत्याकांड की निगरानी नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अब एमएम कलबुर्गी की हत्या मामले की निगरानी नहीं करेगा। कर्नाटक के धारवाड़ में 30 अगस्त 2015 को साहित्यकार कलबुर्गी की हत्या कर दी गई थी। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने पाया कि मामले में सत्र अदालत में सुनवाई के लिए आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा कि राज्य हाई कोर्ट भी मामले की प्रगति की निगरानी बंद कर चुका है। विशेष जांच टीम ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि मामले के दो मुख्य आरोपित फरार हैं। (आइएएनएस)

रक्षा भागीदारी के लिए ब्रिटेन ने दिया संप्रभु गारंटी का प्रस्ताव

तैयारी ▸ लखनऊ डिफेंस एक्सपो में रक्षा खरीद मंत्री के साथ आएगा बड़ा दल

साझेदारी को विश्वसनीयता देने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा भारत

संजय मिश्र, नई दिल्ली

सैन्य आधुनिकीकरण की गति को रफ्तार दे रहे भारत के साथ रक्षा साझेदारी ब्रिटेन की अहम रणनीतिक नीति का हिस्सा बन गई है। इस रणनीति के तहत ब्रिटिश रक्षा उत्पादकों के साथ साझेदारी व सहयोग के लिए ब्रिटेन भारत को संप्रभु गारंटी देने को तैयार है। रक्षा साझेदारी को पारदर्शिता और विश्वसनीयता देने के लिए संप्रभुता की गारंटी के इस प्रस्ताव पर भारत विचार कर रहा है। सैन्य और रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बड़ी संभावनाओं को देखते हुए ही फरवरी में लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो में शामिल होने के लिए ब्रिटिश रक्षा खरीद मंत्री की अगुआई में एक हाईप्रोफाइल दल भी आ रहा है।

भारत-ब्रिटेन के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए वैसे भी फरवरी में दोनों देशों की सेना 'अजय योद्धा' के तहत संयुक्त अभ्यास करेंगी। इसमें आतंकवाद से मुकाबले की सैन्य रणनीति पर फोकस होगा। इसमें रायल ब्रिटिश एयरफोर्स के रक्षा बल और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो दस्ते साझा अभ्यास करेंगे। वहीं ब्रिटिश नौसेना इस साल भारत में 'मिलन' अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास करेगी।

भारत की तीनों सेनाओं और सरकार के साथ सैन्य व रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहे इन सहयोगों की चर्चा करते हुए ब्रिटेन के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर गेविन थामसन ने बातचीत में रक्षा सहयोग के लिए भारत को संप्रभु गारंटी की पेशकश किए जाने की पुष्टि की। उनके मुताबिक रक्षा मंत्रालय इस पेशकश पर विचार कर रहा है। रक्षा सौदों और साझेदारी को बिचौलिए के विवादों से बचाने के लिए भारत ने निजी विदेशी कंपनियों से खरीद को दोनों राष्ट्रों के बीच समझौते के कवच में लाने का सिलसिला शुरू किया है। भारत-फ्रांस के बीच दासौ कंपनी से राफेल जेट खरीद के समझौते से इसकी शुरुआत हो चुकी है।

थामसन ने कहा कि भारत के साथ सैन्य सहयोग केवल रक्षा खरीद-बिक्री का नहीं बल्कि बराबर की मजबूत साझेदारी से जुड़ा है। ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को साकार करने के लिए भागीदार बनने को तैयार है। इसके मद्देनजर ही लखनऊ डिफेंस एक्सपो में ब्रिटेन की रक्षा क्षेत्र की तमाम बड़ी कंपनियां जैसे एयर बस, थेल्स, बेएई सिस्टम, राल्स रॉयस शामिल हो रही हैं। थॉमसन ने कहा कि ब्रिटिश नौसेना के 65 हजार टन क्षमता वाले दो नए एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस विलियम्स में भारतीय नौसेना ने शुरुआती रुचि दिखाई है। भारतीय नौसेना भी इस क्षमता के एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है। इस लिहाज से दोनों देशों के बीच इसमें सहयोग की काफी गुंजाइश है। ब्रिगेडियर गेविन थॉमसन ने कहा कि ये दोनों ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से कीमत में 30 फीसद कम हैं, तो इनका परिचालन खर्च भी कम है। साथ ही संचालन के लिए मानव संसाधन की संख्या भी कम चाहिए। ऐसे में यह काफी सस्ता है।

भारत में ब्रिटेन के रक्षा और सुरक्षा संगठन के प्रमुख डामिनिक बेल्स ने कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता निर्यात से बड़ा है। इसीलिए सहयोग-साझेदारी के तहत हम भारत की रक्षा जरूरतों का निर्माण यहीं करने को प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश उद्योग जगत भी अब मान रहा है कि भारत में कारोबार की राह आसान हुई और ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बढ़ी है।

बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की पहली बुलेट ट्रेन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तकनीकी आधार पर चुनौती देने वाली याचिकाओं को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने को सर्वोच्च अदालत ने मंजूरी दी है।

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना पर शुक्रवार को जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में केंद्र, गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 सितंबर को भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अंतरिम राहत के तौर पर याचिका में बुलेट ट्रेन के लिए गुजरात सरकार के जरिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रोकने की अपील की गई है। विशेष अनुमति याचिकाओं में कहा गया है कि केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए। ऐसा बुलेट ट्रेन परियोजना को सही वक्त पर पूरा करने के लिए जरूरी है। इस परियोजना से लोगों को फायदा होगा।

बुलेट ट्रेन परियोजना तो प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबी के साथ मिलकर सितंबर, 2017 में लांच किया था। यह ट्रेन 320-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अहमदाबाद-मुंबई के बीच 508 किमी की दूरी को तय करेगी। इस बीच यह 12 स्टेशनों पर रुकेगी।

भारत की कश्मीर नीति पर कोई शक नहीं : रूस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- रूसी उप राजदूत ने कहा, इसे संयुक्त राष्ट्र में नहीं उठाया जाना चाहिए
- भारत के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम एस-400 का निर्माण भी शुरू

कश्मीर मुद्दे पर रूस ने साफ कर दिया है कि वह भारत की मंशा पर कोई शक नहीं करता। दो दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत व रूस के रिश्ते को इस सदी की सबसे अलग किस्म की दोस्ती करार दिया था। शुक्रवार को भारत में रूस के उप राजदूत रोमन बाबुशकिन ने इसे फिर साबित किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कश्मीर की यात्रा करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर दोस्त के तौर पर आमंत्रित किया जाता है, तो निश्चित तौर पर हम जाएंगे। लेकिन वहां नहीं जाने के बावजूद हम भारत की कश्मीर नीति का समर्थन करते हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका समेत कुछ अन्य देशों के राजदूतों के कश्मीर जाने पर टिप्पणी की है। बाबुशकिन ने कहा, 'कश्मीर वे जाएं जिन्हें शक हो। रूस मानता है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, जिसे उन्हें शिमला समझौते व लाहौर घोषणापत्र के हिसाब से सुलझाना चाहिए। इसे कभी संयुक्त राष्ट्र में नहीं उठाया जाना चाहिए।'

बाबुशकिन ने भारत की हर रक्षा जरूरत को भी पूरा करने की बात कही। अमेरिका के विरोध के बावजूद जिस तरह से भारत रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम एस-400 खरीदने पर अड़ा हुआ है, रूस सरकार उसका बेहद सम्मान करती है। रूस ने भारत के लिए इस सिस्टम को बनाना भी शुरू कर दिया है।

रूस के उप राजदूत ने बताया कि वर्ष 2025 में भारत को दिए जाने वाले एस-400 का निर्माण शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक इस तरह के पांच सिस्टम भारत को दिए जाएंगे, जिसकी अनुमानित लागत 25 हजार करोड़ रुपये है। यह सिस्टम भारत को दुश्मन देशों के मिसाइल हमले से बचाने में मदद करेगा। दो दिन पहले ही रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ जयशंकर की द्विपक्षीय मुलाकात हुई है, जिसमें इस बारे में बातचीत हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर मार्च में रूस का दौरा करेंगे जहां भारत, रूस और चीन के त्रिपक्षीय गुट की भी बैठक होगी।

रोमन बाबुशकिन। फाइल

कामथ और स्वप्न दासगुप्ता बन सकते हैं मोदी कैबिनेट का हिस्सा

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में तकनीक के माहिर दो लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। ब्रिक्स बैंक (डेवलेपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज) के चेयरमैन कुंडापुर वमन कामथ और भाजपा के राज्यसभा सदस्य स्वप्न दासगुप्ता को अहम भूमिका मिल सकती है।

उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि वयोवृद्ध बैंकर केवी कामथ बतौर वित्त राज्यमंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राजनीति के क्षेत्र में पहला कदम रखने वाले कामथ की भूमिका आगे चलकर बढ़ाई भी जा सकती है। कामथ आइसीआइसीआइ बैंक और इंफोसिस के चेयरमैन रह चुके हैं। उनकी भारतीय उद्योग जगत में गहरी पैठ भी है।

दूसरी ओर, दासगुप्ता दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। उन्हें मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास के राज्यमंत्री के तौर पर शामिल किया जा सकता है। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में अफरातफरी के माहौल के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय की घेराबंदी तेज हो गई है। लिहाजा उनकी नियुक्ति भी खासी अहम होगी।

अगर सरकार तकनीक के क्षेत्र में अपने विशेषज्ञों की जमात को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रही तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के नाम पर भी विचार हो रहा है। पहले वाणिज्य, उद्योग और रेल मंत्रालय संभाल चुके सुरेश प्रभु की भी मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है।

मोदी सरकार-1 में हरदीप पुरी, केजे अल्फोंज और एमजे अकबर जैसे तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया था। लेकिन कामथ को वित्त मंत्रालय में लाना सरकार का एक अहम संकेत होगा। चूंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नार्थ ब्लाक में अब तक सिर्फ राजनेता ही हैं। जबकि सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं आया है, सरकार अनुभवी नीति निर्माताओं की तलाश में है। ताकि अर्थव्यवस्था के डांवाडोल जहाज को आगे बढ़ने के लिए रफ्तार दी जा सके।

केवी कामथ।

स्वप्न दासगुप्ता। फाइल

- ब्रिक्स बैंक के चेयरमैन कामथ बन सकते हैं वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री
- भाजपा सांसद स्वप्नदास बन सकते हैं एचआरडी में जूनियर मंत्री

हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग पर फैसला ले केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय के प्रतिवेदन पर तीन माह के भीतर फैसला लेने के लिए कहा है। भाजपा नेता ने देश की हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। जस्टिस एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्कूल कहां खुले यह फैसला कोर्ट नहीं कर सकता।

पीठ ने कहा, 'हालांकि हम निर्देश दे रहे हैं कि आपके आवेदन पर तीन महीने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय फैसला लेगा।' उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। देश के हर राज्य की हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए जाने की जरूरत है। इससे गरीब वर्ग के बच्चों को मदद मिलेगी। पिछले साल अक्टूबर में हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय विद्यालय खोलने का मुद्दा एक नीतिगत फैसला है और पीआइएल में उठाए गए मुद्दे पर फैसला सरकार पर छोड़ा जाए।

कार्ति चिदंबरम को 20 करोड़ लौटाने की अनुमति : वहीं, एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को 20 करोड़ रुपये वापस लेने की अनुमति दे दी है। कांग्रेस नेता ने विदेश यात्रा की अनुमति देने की शर्त के तहत शीर्ष कोर्ट रजिस्ट्री में यह राशि जमा कराई थी।

अगले सोमवार को ही भाजपा अध्यक्ष बनेंगे जेपी नड्डा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मतदान होने की स्थिति में मंगलवार को आएगा नतीजा

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और सांसद राधामोहन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सोमवार 20 जनवरी को नामांकन से लेकर नाम वापसी तक की प्रक्रिया होगी और जरूरी हुआ तो अगले दिन मतदान होगा। वैसे माना जा रहा है कि नड्डा निर्विरोध सोमवार को ही अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे।

भाजपा संविधान के अनुसार कम से कम आधे राज्यों में सांगठनिक चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। राधामोहन सिंह ने जानकारी दी कि आधे से ज्यादा 21 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का चुनाव हो गया है। इस बार सांगठनिक चुनाव की बड़ी बात यह है कि देश के लगभग साढ़े दस लाख बूथों में से करीब साढ़े सात लाख बूथों पर चुनाव संपन्न हो गया है। यानी लगभग 75 फीसद बूथों पर संगठन सक्रिय है। यह आंकड़ा तब है जबकि चार राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया नहीं हुई है। बहरहाल, चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 20 जनवरी को 10 बजे से 12.30 बजे तक नामांकन करने की प्रक्रिया होगी। 12.30 से एक घंटे तक नामांकन पत्र की जांच होगी और 1.30 से अगले एक घंटे तक का वक्त नामांकन वापसी के लिए रखा गया है। जाहिर है कि सोमवार 12.30 तक अगर एक ही नाम रहा तो उसी वक्त नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। वरना मंगलवार को मतदान किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार अभी तक किसी ने भी फार्म नहीं लिया है। नड्डा के पक्ष में कई सेट भरे जाएंगे। ध्यान रहे कि वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह की जगह नड्डा को संगठन में लाने की बात तभी तय हो गई थी जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के बजाय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

जेपी नड्डा। फाइल

बागवानी में आधुनिक तकनीक की सख्त जरूरत : तोमर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी फसलों को कृषि क्षेत्र के लिए महायोगदान बताते हुए कहा कि इसमें आधुनिक तकनीक की सख्त जरूरत है, जिसे किसानों तक पहुंचाना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। देश को कुपोषण से मुक्त बनाने में फसल और सब्जियां सबसे मुफीद साबित हो सकती हैं। तोमर शुक्रवार को यहां पहली बार आयोजित जायद सीजन की तैयारी बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में रबी और खरीफ के बाद पहली बार जायद व बागवानी की तैयारी बैठक का आयोजन किया गया है। रबी और खरीफ सीजन के बीच के तीन महीने की अवधि में दलहनी फसलें मूंग और उड़द की खेती के साथ तिलहनी सूरजमुखी की खेती भी होती है। इसके साथ सीजनल सब्जियों और फलों की खेती भी की जाती है। परंपरागत फसलों की खेती के साथ इन फसलों से किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है। आधुनिक तकनीक से बागवानी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर देते हुए तोमर ने कहा कि वैज्ञानिकों की इजाद को किसानों तक पहुंचाने में राज्यों की अहम भूमिका होती है। राज्यों के प्रतिनिधियों से चर्चा में उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें विशेष प्रयास करने होंगे।

बुजुर्गों की चिंता

इस योजना की लोकप्रियता का एक बड़ा पहलू यह भी है कि इसके तहत बुजुर्गों को वे उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिसकी बुढ़ापे में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है

वयोश्री योजना को सरकार दे सकती है और रफ्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सभी जिलों में इसे लागू करने का हो सकता है एलान, अभी सिर्फ 329 जिलों में है लागू
- बैंकों में जमा अनक्लेम फंड से ऐसी योजनाओं का होता है संचालन

बुजुर्गों से जुड़ी राष्ट्रीय वयोश्री योजना को सरकार अब और रफ्तार दे सकती है। बजट में इसे देश के सभी जिलों में लागू करने जैसी घोषणाएं हो सकती हैं। फिलहाल देश के सिर्फ 329 जिलों में ही यह लागू है। हालांकि इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि लगभग सभी सांसदों ने इसे अपने क्षेत्रों में भी शुरू करने की मांग की है। वैसे भी इसे विस्तार देने से सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका संचालन बैंकों में पड़े हजारों करोड़ के अनक्लेम्ड फंड से किया जाता है। ऐसे में इसकी राह में फिलहाल कोई बड़ी अड़चन नहीं दिख रही है।

इस योजना की लोकप्रियता का एक बड़ा पहलू यह भी है कि इसके तहत बुजुर्गों को वे उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिसकी बुढ़ापे में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इनमें चश्मा, सुनने की मशीन, छड़ी, वॉकर, व्हील चेयर, दांत व ट्राई पॉड्स आदि उपकरण प्रमुख हैं। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की मानें तो इसकी राह में सिर्फ उपकरणों की आपूर्ति ही एक अड़चन है। इससे योजना को एक साथ सभी जिलों में लागू करने में आपूर्ति का संकट खड़ा हो सकता है। इन उपकरणों का निर्माण सिर्फ एलिम्को (आर्टीफिशियल लिंबस मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया) ही करता है। मौजूदा समय में जिन जिलों में यह योजना लागू है, वहां भी समय से उपकरणों के पहुंचने में कठिनाई हो रही है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो इस बीच एलिम्को ने कई नई यूनिटें भी शुरू की हैं, जहां उत्पादन शुरू हो गया है। ऐसे में उपकरणों की आपूर्ति को लेकर अब कोई संकट नहीं रहेगा।

सूत्रों की मानें तो देश के अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों में मौजूदा समय में करीब 32 हजार करोड़ रुपये का अनक्लेम्ड फंड मौजूद है।

वैसे भी सरकार का बुजुर्गों पर खास ध्यान है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, देश में बुजुर्गों की कुल संख्या करीब 11 करोड़ है जो 2026 तक करीब 17 करोड़ तक होने का अनुमान है। सरकार हाल ही में बुजुर्गों की देखरेख को लेकर संसद में एक सख्त कानून लेकर आई है। उम्मीद है, कि वह संसद के बजट सत्र में पारित हो जाएगा।

प्रतीकात्मक।

बंगाल में दिलचस्प होगी रास चुनाव की लड़ाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में राज्यसभा के लिए पांच सीटों पर आगामी अप्रैल माह में होने वाले चुनाव में लड़ाई दिलचस्प होगी। इनमें चार सीटें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में थीं, जबकि एक पर माकपा काबिज थी। हालांकि, माकपा ने दल विरोधी कार्य के चलते अपने राज्यसभा सदस्य ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया था और ऋतब्रत ममता के खेमे में चले गए थे। ऐसे में यूं कहें तो कुल मिलाकर पांचों ही सीटें तृणमूल के पास ही थीं।

राज्यसभा सदस्य ऋतब्रत बनर्जी (माकपा से निष्कासित) और चार तृणमूल के केडी सिंह, अहमद हसन इमरान, जोगेन चौधरी व मनीष गुप्ता का कार्यकाल दो अप्रैल 2020 को समाप्त हो जाएगा। राज्य विधानसभा में दलगत स्थिति ऐसी है कि अपने बलबूते माकपा या फिर कांग्रेस या भाजपा एक भी प्रत्याशी को नहीं जीता पाएंगे। क्योंकि, इस समय तृणमूल के पास विधायकों की संख्या 222 है। वहीं, पूरे वाममोर्चा के विधायकों संख्या 30 के पार भी नहीं है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी